साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 310 | जौनपुर, मंगलवार, 06 अगस्त 2024 | साान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

बाढ़ प्रभावित लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी - योगी

कुशीनगर, संवाददाता । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि नारायणी और गंडक नदी में बाढ़ से बचाव के लिए बीते सात साल में बड़े स्तर पर प्रयास किये गये हैं। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि वह नारायणी नदी पर पक्का पुल बनाने के लिए सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द शुरू करें। मुख्यमंत्री ने आमजन को भरोसा देते हुए कहा कि आपको कोई परेशानी न हो, आपकी हर समस्या के समाधान के लिए ये सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित हर व्यक्ति की सुरक्षा और सहायता के लिए सरकार 24 घंटे खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने रविवार को जिले की ग्रामसभा तुर्कहा में बाढ़ प्रभावित

लोगों से मुलाकात की और राहत सामग्री का वितरण किया। लखनऊ में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इससे पहले भैंसहां–छितौनी तटबंध का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किया। साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया और टॉफी देकर उनको दुलार–प्यार किया। योगी ने कहा, करीब 600 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करते हुए बाढ़ से बचाव के विभिन्न प्रबंधन करने का ही परिणाम है कि 83 गांव की 1,16,000 की आबादी और 20 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि सुरक्षित हुई है। उन्होंने कहा कि नारायणी के उस पार करीब 20 हजार की आबादी को इस पुल से बहुत फायदा मिलेगा, ऐसे में बाढ़ का पानी उतरते ही नदी पर जहां पुल बनाया जाना है, इसका सर्वे कराकर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। उन्होंने कहा कि आपदा में सरकार 24 घंटे अपने नागरिकों की सहायता और सुरक्षा के लिए खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले सात साल में समय पर बाढ़ से बचाव के उपाय करने का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर जनधन की हानि को रोकने में मदद मिली है। अकेले कुशीनगर में करीब तीन लाख की आबादी को बाढ़ से बचाने में भी मदद मिली। इसी का परिणाम है कि न केवल हम यहां सुरक्षित और निश्चिंत हैं, बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बाढ़ से बचाव को लेकर कार्य हुए हैं। योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में पूरी दुनिया इसे शांति की भूमि के रूप में देखती है। इसे दुनिया की आस्था का केंद्र बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी – प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली, एजेसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि देश की संसद द्वारा पांच साल पहले आज ही के दिन संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त कर दिया गया था जो हमारे देश के इतिहास में एक 'ऐतिहासिक क्षण' था। उन्होंने कहा, ''यह जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी। इसका मतलब था कि भारत के संविधान को इन स्थानों पर, संविधान बनाने वाले महान पुरुषों और महिलाओं की दृष्टि के अनुरूप अक्षरशः लागू किया गया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही उन महिलाओं, युवाओं, पिछड़ों, आदिवासियों और हाशिए के समुदायों को सुरक्षा, गरिमा और अवसर मिला जो विकास के लाभ से वंचित थे। साथ ही इसने यह सुनिश्चित किया कि जम्मू एवं कश्मीर को भ्रष्टाचार से दूर किया जाए जिसने दशकों से इस पूर्ववर्ती प्रदेश को त्रस्त कर रखा था। उन्होंने कहा, ''मैं जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।

विदेश मंत्री से मिले राहुल, हम भारत सरकार के साथ

नई दिल्ली, एजेसी। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के मानसून सत्र से इतर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों ने

बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। कांग्रेस सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदंबरम ने कहा कि हमें यह देखने को मिला कि वर्तमान स्थिति हमारी सीमा सुरक्षा को कैसे प्रभावित करने वाली है। यदि बांग्लादेश में कोई भारतीय नागरिक हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सभी सुरक्षित हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम यह भी सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश से हमारी सीमाओं में आने वाले शरणार्थियों की कोई आमद न हो। सभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे हित सर्वोपरि हैं, राजनीतिक दल भारत सरकार के पीछे एकजुट होंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार देश को मौजूदा स्थिति से अवगत कराये। बांग्लादेश में रहने वाले सभी भारतीय सुरक्षित रहें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन के कक्ष में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में हुए हालात की जानकारी दी है। पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा की खबर है। भारत का स्टैंड पूरे मुद्दे पर क्या होगा। भारत रणनीतिक, राजनयिक और सैन्य तौर पर कैसे आगे बढ़ेगा।

जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ लोकतंत्र - शाह

नई दिल्ली, एजेसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है और क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे होने पर, शाह ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक–आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास एक शानदार प्रयास बन गए हैं। शाह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35ए को ऐतिहासिक रूप से हटाए जाने के पांच साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू–कश्मीर और लद्दाख में

जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है। उन्होंने आगे लिखा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक–आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। भाजपा नेता ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के पांच साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कदम देश के लोकतंत्र और जम्मू–कश्मीर के लिए ठीक नहीं था। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। मेहदी ने लोकसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ''जो पांच अगस्त को हुआ था, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था...किसी पार्टी के लिए ठीक हो सकता हैं।

न्यूज डायरी

ई रजिस्ट्री वाला यूपी बना देश का दूसरा राज्य

लखनऊ, संवाददाता। अब संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार आफिस जाने की जरूरत नहीं है। शुरुआत सरकारी विभाग से हो गई है। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों, आवास विकास सहित् संपत्ति का लेनदेन करने वाले विभागों में ई रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी गई है। ये शुरुआत करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बन गया है। अभी तक ई रजिस्ट्री की सुविधा केवल महाराष्ट्र में ही थी। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या सरकारी विभागों से जुड़ी संपत्ति की है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत

नई दिल्ली, एजेसी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि वह जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने को केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी।

विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ अलोकतांत्रिक व पक्षपातपूर्ण व्यवहार

जयपुर, एजेंसी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के अनेक नेताओं ने विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से निलंबित किए जाने की आलोचना की है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ 'अलोकतांत्रिक व पक्षपातपूर्ण' व्यवहार किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़े एक मुद्दे को लेकर हुए हंगामे व नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर को सदन से निलंबित करने की घोषणा की। बाद में भाकर को सदन से निकालने के लिए आए मार्शलों व कांग्रेस विधायकों में धक्का मुक्की हुई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा, "पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकरका निलंबन तथा जबरन निष्कासन फिर मार्शलों द्वारा वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा को जमीन पर गिराना व विधायक अनिता जाटव से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने लिखा, "यह राज्य की भाजपा सरकार की तानाशाही सोच का नतीजा है जिसके कारण चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। विधान सभा में प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ जिस प्रकार का अलोकतांत्रिक व पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने एक्स पर लिखा, "भाजपा सरकार सदन की गरिमा खत्म करने पर तुली है।

केंद्र सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण कर अपनी राजनीति करना चाहती है - तेजस्वी यादव

पटना, एजेसी। वक्फ एक्ट में संशोधन करने के सवाल पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्र पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक बात समझने

वाली यह है कि केंद्र सरकार को जनहित के कार्य नहीं करने हैं। उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ ध्रुवीकरण कर हिंदू–मुसलमान कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। बिहार जो पिछड़ा हुआ है, इसकी भलाई के लिए केंद्र ने कितने कारखाने लगाए। भाजपा के लोगों को पहले बताना चाहिए कि जो आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाया है उसे वे 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे हैं। बिहार आते हैं तो बड़े–बड़े वादे करते हैं, लेकिन बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के वादे का क्या हुआ। हालांकि, तेजस्वी यादव ने वक्फ एक्ट में संभावित संशोधन पर खुलकर बयान नहीं दिया। दावा किया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है। अगर संशोधन बिल पारित होता है तो यह तीसरी बार होगा जब एक्ट में संशोधन किया जाएगा। पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। जिसमें संशोधन 1995 में किया गया। इसके बाद साल 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया था। 2024 में यह तीसरी बार संशोधन किया जा सकता है। एक्ट में संशोधन होने पर वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों का ब्योरा जिला अधिकारी के पास देना होगा। एक्ट में संशोधन नहीं होने तक किसी तरह का कोई ब्योरा नहीं दिया जाता है।

केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ – ममता

शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा देने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की खबर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि यह दो देशों के बीच का मामला है, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर निर्णय लेगी कि इस मुद्दे पर कैसे संपर्क किया जाए और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की जाती है कि वे भड़काऊ टिप्पणियां करने से बचें जो बंगाल या देश में शांति को बाधित कर सकती हैं। ममता ने कहा कि कुछ भाजपा नेता पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो गई। हम मीडिया से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आई हैं क्योंकि उनका भी मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध साझा करता है। हम यथाशीघ्र सामान्य स्थिति लौटने की आशा करते हैं। जरूरत पड़ने पर हमारे पीएम इस मामले में जरूर दखल देंगे। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकीं शेख हसीना के लंदन रवाना होने की जानकारी है।

मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं – शिवराज

नई दिल्ली, एजेसी। राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को किसानों की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं।

जब कांग्रेस अलग–अलग राज्यों में सत्ता में थी, तब किसान मारे गए थे। इनके सामने दिग्विजय सिंह बैठे हैं, इनके हाथ खून से सने हैं। 24–24 किसानों को मारा गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस शासन के दौरान हुए गोलीकांड को गिनाते हुए कहा कि साल 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी।

लोगों की सेहत मोदी सरकार की प्राथमिकता, स्वास्थ्य बजट में 164 प्रतिशत की बढ़ोतरी

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों के स्वास्थ्य को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए दावा किया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भारत में चलाई जा रही है और स्वास्थ्य बजट के आवंटन में भी 164 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ घोषणाएं ही नहीं करती, बल्कि उसे धरातल पर सफल बनाने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से काम करती है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार सक्रिय और प्रतिक्रियाशील रही है। वर्ष 2013–14 में स्वास्थ्य का जो बजट 33,278 करोड़ रुपए था, आज उस बजट को बढ़ाकर 90,958 करोड़ रुपए कर दिया गया गया है। स्वास्थ्य बजट के इस आवंटन में 164 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के बजट में यह बढ़ोतरी लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल को प्राथमिकता देने और भारतीयों नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नड्डा ने कहा कि एनडीए की पहली सरकार (अटल बिहारी वाजपेयी सरकार) से पहले देश में एक एम्स था, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान 6 एम्स खोले गए। वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल

में 22 एम्स को मंजूरी दी गई, जिसमें से 18 ऑपरेशनल और 4 निर्माणाधीन हैं। अपने जवाब के दौरान विपक्षी दलों के हंगामे पर सदन में पलटवार करते हुए नड्डा ने कहा कि राजनीति करनी है तो करिए और सच्चाई सुननी है तो सुनिए। बीमारी से संबंधित आंकड़ों को केंद्र के साथ शेयर नहीं करने का आरोप लगाया।

वक्फ कानून में संशोधन का विरोध करेंगे अखिलेश

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने के केंद्र के कदम का विरोध करेगी। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि भाजपा के पास हिंदू–मुसलमान या मुस्लिम भाइयों का हक कैसे छीना जाए इसके अलावा कोई काम नहीं है। उन्हें जो अधिकार मिले हैं, आजादी का अधिकार या अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, अपनी कार्य प्रणाली को कायम रखने का अधिकार। अखिलेश ने आगे कहा कि उन्हें (सीएम योगी आदित्यनाथ) पता चला कि नजूल एक उर्दू शब्द है, अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और है. लेकिन उनका मानना था कि नजूल का मतलब मुसलमानों

की जमीन है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आरक्षण, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों की चिंता है उन्हें तुरंत बीजेपी छोड़ देनी चाहिए। सपा नेता ने कहा कि एक स्टूल–किट नेता हैं...उन्हें जाति जनगणना और आरक्षण के बारे में बात करनी चाहिए। पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की, ने कहा, बीजेपी का एक ही काम है हिंदू और मुसलमानों को बांटना, मुस्लिम भाइयों का हक छीनना और संविधान में जो हक दिया गया है।

संपादकीय

बरसात के दिनों का अधिकतम लाभ उठाए

पिछले महीने एक मंगलवार की शाम को एक जोड़ा आया जिसे मैं और मेरी पत्नी प्रीता अच्छी तरह से जानते हैं। चूँकि हमें उनकी संगति अच्छी लगती है, इसलिए हमने सोचा कि हम उनका स्वागत एक शानदार डिनर के साथ करेंगे। इसलिए हमने मंगलवार की दोपहर का अधिकांश समय कुछ ऐसा बनाने में बिताया जिसे हम जानते थे कि वे पसंद करेंगे, एक मलाईदार बेक्ड चिकन डिश।प्रीता इसे बनाने का तरीका श्रमसाध्य है, लेकिन परिणाम सार्थक हैं। उस शाम छह बजे तक, हम पूरी चीज को ओवन में डालने के लिए तैयार थे, तभी अचानक बारिश आ गई, और उसके बाद, जैसा कि इन इलाकों में आम है, बिजली चली गई। हम चिंतित नहीं थे, क्योंकि आमतौर पर तूफान के गुजरने के आधे घंटे बाद बिजली आ जाती है। मैंने बिजली कंपनी के कॉल सेंटर को फोन किया, और बताया गया कि कहीं कोई खराबी है, और सामान्य आधे घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। आधा घंटा बीत गया, और हमारे आगंतुकों का समय आ गया, लेकिन बिजली नहीं थी। मैंने दूसरी बार फोन किया, और बताया गया कि इसमें कुछ और घंटे लगेंगे। इस समय, हमें अपने द्वारा तैयार किए गए चिकन से कुछ खाने योग्य बनाने के लिए आपातकालीन उपाय करने थे, इसलिए प्रीता ने ऐसा किया। बिजली आने से पहले ही हमारे मेहमान आ गए। हमारे पास लाइट और पंखे थे, और हमारे चतुर मित्रों ने दावा किया कि उन्हें क्रीमी करी चिकन लगभग उतना ही पसंद आया जितना कि उसका बेक्ड कजन। मुझे खेद है लेकिन हमारे पास बिजली नहीं थी, प्रीता ने उनसे कहा, हम इसे कल रात खाएंगे। उसे विश्वास था कि वह ऐसा कर सकती है क्योंकि हालाँकि बिजली कंपनी हर बुधवार को सुबह 10 बजे बिजली काट देती है, लेकिन वे इसे शाम 5 बजे बहाल कर देते हैं। जब हम आधी रात के बाद बिस्तर पर गए तो बिजली अभी भी वापस नहीं आई थी। अगली सुबह लगभग नौ बजे बिजली बहाल हुई, जब हम देर से नाश्ता कर रहे थे, और मैंने यह सुनिश्चित करने के लिए माफी मांगी कि ओवरहेड टैंक भरा हुआ है और वॉशिंग मशीन चालू है। तीन चौथाई घंटे बाद, वॉश साइकिल पर सिर्फ तीन मिनट शेष रहते, बिजली फिर से चली गई, इस बार बिना किसी तरह के तूफान के। कॉल सेंटर में हमारे मित्रों ने मुझे बताया कि यह नियमित रखरखाव आउटेज था। पूरी रात बिजली न आने के बाद पूरे दिन बिजली न आने से प्रीता परेशान थी, लेकिन उसने ज्यादा चिंता नहीं की। शाम के 5 बजे का वादा किया गया समय शाम के 6 या 7 बजे तक भी बढ़ सकता था, बिना हमारे शाम के मेनू को प्रभावित किए। लेकिन जब शाम 6 बजे तक बिजली नहीं लौटी, तो मैंने अपने दोस्तों को फिर से फोन किया, और बताया गया कि मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिजली कब वापस आएगी। अब तक हम सुबह के 45 मिनट के एक छोटे से अंतराल को छोड़कर 24 घंटे से अधिक समय से बिजली के बिना रह चुके थे। प्रीता अपना काम फ्रिज में रखने और एक अच्छे रेस्तरां से डिनर ऑर्डर करने के लिए तैयार थी, लेकिन फ्रिज भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए, लगातार दूसरी रात, हमें मलाईदार करी से काम चलाना पड़ा। अगली सुबह, हमारे मेहमानों को सुबह के समय ही चले जाना था। उन्हें कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि वे केवल तीन घंटे की दूरी पर रहते हैं और हम अभी भी साथ रहने का आनंद ले रहे थे। इसके अलावा, जब हम अभी भी सो रहे थे, तब बिजली छोटे घंटों में वापस आ गई थी, और उन्होंने घर में पके हुए ब्रेड और तले हुए अंडे के नाश्ते के लिए बैठने से पहले गर्म स्नान का आनंद लिया था। इस सुखद दृश्य में मेरे फिक्सर मित्र मूर्ति एक और आदमी के साथ आए, जिसका नाम वसंत था, वह गठीला और अकड़ता हुआ, वालरस मूंछों वाला और एक अस्पष्ट धमकी भरा अंदाज वाला। मूर्ति ने कहा, ष्एक प्रभावशाली व्यक्ति।ष ष्हमारे पास पास में एक मीटिंग है, और हम जल्दी पहुँच गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आ जाऊँ। मैं उसे ड्रिंक देने ही वाला था – मैंने अपने दोस्तों के लिए कुछ बढ़िया स्कॉच मँगवाई थी – जब उसने कहा। ष्एक कप चाय भी ठीक रहेगी। तुम भाग्यशाली हो, मैंने उससे कहा, षकि हमारे पास बिजली है। क्यों? उसने पूछा। मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से बिजली गुल होने के बारे में बताया। ज्यादातर बिजली कंपनी में भ्रष्टाचार के कारण, मेरे मित्र, जो एक इंजीनियर हैं, ने कहा। आप देख सकते हैं कि वे जिस सामग्री का उपयोग करते हैं, शीट मेटल और केबल और यहाँ तक कि खंभे, उसकी गुणवत्ता कहीं से भी अपेक्षित नहीं है। इसलिए विफलताओं के बीच हमारा औसत समय आधे से भी कम है, जिसके सभी सामान्य परिणाम हैं। लंबे समय तक बिजली गुल होना, कम उत्पादकता और हर तरफ अधिक लागत। तटीय इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं, क्योंकि हर चीज में जंग जल्दी लगती है। वसंत ने पूछा, आप इसे खराब कैसे कह सकते हैं? हम 30 घंटे से बिजली के बिना हैं। मेरे दोस्त ने कहा। ष्कल्पना कीजिए कि एक छोटी फैक्ट्री चार शिफ्टों तक बिजली के बिना रहे। आप सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं, वसंत ने कर्कश आवाज में कहा। ष्यह एक समाज है। दूसरी चीजें भी मायने रखती हैं। क्या? मेरे दोस्त ने पूछा। ष्नौकरी और व्यापार की तरह, वसंत ने कहा। देखिए, जहाँ सिर्फ तीन लाइनमैन की जरूरत है, वहीं सरकार बारह लोगों को काम पर रखती है। उन सभी को काम करना पड़ता है, है न? हमारे यहाँ कई बैटरी कंपनियाँ हैं। इन्वर्टर कंपनियाँ। सभी छोटे पैमाने की। सभी में सर्विस करने वाले लोग हैं।

नीरस बहस विधायी गिरावट की ओर इशारा करती

विनोद

यह देखकर दुख होता है कि संसद हो या राज्य विधानसभा, विधानमंडलों में मानकों का किस तरह पतन हो रहा है। वे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय एक–दूसरे पर निशाना साधने और तरह–तरह के आरोप लगाने के मंच में तब्दील हो रहे हैं। दूसरे पक्ष का मुकाबला करने की रणनीति बहुत व्यक्तिगत होती जा रही है। ऐसा लगता है कि प्रतिद्वंद्वी सदस्यों पर कीचड़ उछालने के लिए संबंधित राजनीतिक दलों के शोध विंग और पटकथा लेखकों द्वारा खोजे गए आंकड़ों से लैस होकर दमखम की जरूरत है। विधानमंडलों में यह असामान्य नहीं है, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वियों को फटकारने में सांसदों को कमतर नहीं आंकना चाहिए। पहले कभी बहस इतनी नीरस और नीरस नहीं रही। 2024–25 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित नहीं थी। वे राजनीति से प्रेरित भाषण थे। आश्चर्य होता है कि क्या कोई जानता है कि कम से कम उनके निर्वाचन क्षेत्र के लिए बजट का क्या मतलब है। इस प्रक्रिया में, महाभारत और रामायण को भी इन चर्चाओं में घसीटा जा रहा है और सांसद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यह सोचकर कि उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया था। ऐसा लगता है कि कोई भी इस बात पर आत्मचिंतन नहीं करता कि क्या वे आम आदमी के लिए कोई मायने रखते हैं या फिर यह आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने में किस तरह योगदान देता है। 'कुर्सी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी अब या 2029?' यह विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के लिए 'कुर्सी कैसे बचेगी 2029?' दोनों के लिए मुख्य चिंता का विषय है। राहुल गांधी के भाषण में जाति जनगणना को मजबूर करने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। उन्होंने चक्रव्यूह, कौरव, दुशासन, कर्ण, दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बात की। ऐसा लगा जैसे वे खुद को अभिमन्यु के रूप में पहचान रहे थे, जो महाभारत के चक्रव्यूह नामक रूपक में फंसा हुआ है। संसद में जब बजट पर चर्चा होती है, तो उम्मीद की जाती है कि सदस्य आंकड़ों और तथ्यों के साथ पूरी तैयारी के साथ आएंगे, पिछले बजटों के दौरान आवंटन का विश्लेषण करेंगे, पिछले बजटों में कितना पैसा खर्च किया गया, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, सत्ताधारियों को उनके प्रदर्शन के बारे में आईना दिखाएंगे और सुझाव देंगे कि क्या किया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से, अब तक के भाषण राजनीतिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार, 2029 में कौन सत्ता में आएगा, अपने मित्रों को खुश करने और कट पेस्ट बजट जैसी सामान्य टिप्पणियों के इर्द–गिर्द ही रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सदस्यों को दी जाने वाली बजट पुस्तकों का किसी ने अध्ययन नहीं किया है। बेहतर होगा कि सरकार उन्हें छापना बंद कर दे और सदस्यों को केवल ऑनलाइन लिंक दे। इससे कम से कम करदाताओं की मेहनत की कमाई तो बचेगी। नेता अपने–अपने राजनीतिक दलों द्वारा दिए जाने वाले नोटों पर अधिक निर्भर रहते हैं, जो राजनीति से प्रेरित होते हैं और दर्शकों को लुभाने के लिए बनाए जाते हैं। हमने इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, प्रणब मुखर्जी, जयपाल रेड्डी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी जैसे दिग्गज नेताओं और चौधरी चरण सिंह जैसे देहाती नेताओं को देखा है, जो बजट की खामियों और अच्छाइयों को सामने लाते थे और समाधान सुझाते थे। यह सुनकर हैरानी हुई कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट में सभी राज्यों के नाम नहीं हैं। क्या यह अज्ञानता है या बजट को महत्वहीन बनाना? जाहिर तौर पर वह पार्टी के कुछ अपरिपक्व लोगों पर निर्भर थे।

विपक्ष के नेता को छाया प्रधानमंत्री माना जाता है। उन्हें दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए और जब जरूरी हो तो हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार पर बुद्धिमानी से हमला करना चाहिए, न कि चर्चाओं पर हावी होने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कोई भी उत्साहित न हो। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सभी राज्यों के नाम शामिल न करने के विपक्ष के तर्क को तब ध्वस्त कर दिया, जब उन्होंने पिछले तीन दशकों के दौरान प्रत्येक बजट भाषण में कितने राज्यों का उल्लेख किया गया और उन्हें 'हलवा' से वंचित नहीं किया गया। राहुल की 'हलवा' वाली टिप्पणी भी हंसी का पात्र बनती है। बजट से पहले इसे तैयार करने की प्रथा सात दशकों से चली आ रही है। अगर इन सभी वर्षों में लगातार सरकारों द्वारा 'हलवा' ठीक से वितरित किया जाता, तो गरीबी या जाति की राजनीति नहीं होती। उम्मीद है कि उन्हें याद होगा कि 75 वर्षों में ज्यादातर समय कांग्रेस ही सत्ता में रही।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राज्यों को आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बीच उप–श्रेणियाँ बनाने की अनुमति देने का निर्णय अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लागू की गई व्यवस्था के समान है। यह उन जातियों और जनजातियों के लिए 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा प्रस्तुत करता है जिनका सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अधिक प्रतिनिधित्व है। कुछ राज्य पहले ही ऐसा कर चुके हैं। यह उन लोगों के लिए न्याय की तलाश है जो एससीध्एसटी श्रेणी में अन्य लोगों की तुलना में सामाजिक रूप से और प्रतिनिधित्व में अधिक वंचित हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता है कि राज्य यह स्थापित करें कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पिछड़ेपन का परिणाम है। तभी संविधान द्वारा समर्थित भेदभाव के तर्कसंगत सिद्धांत को उप–वर्गीकरण से जोड़ा जा सकता है। कुछ दलित शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया है कि कुछ एससी समूहों की तुलनात्मक समृद्धि या बेहतर प्रतिनिधित्व का मतलब यह नहीं है कि उन्हें सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ऐतिहासिक अन्याय वही रहता है। इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें कोटा का एक छोटा हिस्सा दिया जाता है, तो अन्याय दोगुना हो जाएगा। मुद्दा सरल नहीं है, यह प्रतिनिधित्व की प्राथमिकताओं और ऐतिहासिक अन्याय के बीच झूलता रहता है जो वर्तमान में भी जारी है। असुरक्षाएं अपरिहार्य लगती हैं – या क्या यह एससी/एसटी में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं जो कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को उनके स्थान पर रखने की कोशिश कर रहे हैं? संविधान पीठ के सात न्यायाधीशों में से जिन्होंने उप–वर्गीकरण पर फैसला सुनाया, उनमें से एक न्यायाधीश ने असहमति जताई। उनके अनुसार, राष्ट्रपति की सूचियों में हस्तक्षेप करना संसद का अधिकार क्षेत्र है। अधिक सांसारिक स्तर पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित आंकड़ों की शर्त के कारण समस्या उत्पन्न होती है। उप–वर्गीकरण को निष्पक्ष और गैर–राजनीतिक बनाने तथा असुरक्षाओं को शांत करने का यही एकमात्र तरीका है। फिर भी प्रतिनिधित्व प्रतिशत पर शायद ही कोई ऐसा डेटा हो जिसकी तुलना जाति और जनजाति के अनुसार एससी और एसटी संख्याओं से की जा सके। प्रत्येक राज्य में इन दोनों का पूर्ण मूल्यांकन किए बिना, सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति निरर्थक होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश के पिछले आयोगों की रिपोर्टों का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए अब राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना के लिए अधिक दबाव होने की संभावना है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके शक्तिशाली सहयोगियों ने फैसले का स्वागत किया है, इसलिए प्रतिरोध अजीब लगेगा। अन्य दल भी उत्साहित हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि बिना ठोस आंकड़ों के उप–वर्गीकरण संभव नहीं होगा। अगर न्याय ही साझा लक्ष्य है, तो राजनेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फैसले को लागू किया जा सके।

आरक्षण के लिए इष्टतम स्तर और संतुलित दृष्टिकोण

आदित्य

तत्कालीन आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल कुमुद बेन जोशी, जब भी मुख्यमंत्री एन टी रामाराव से असहमत होती थीं, तो हमेशा यह कहकर अपना बचाव करती थीं कि, "मैं पहले नागरिक हूँ और उसके बाद राज्यपाल।" 2001 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जे एस वर्मा और केंद्रीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने नस्लवाद पर संयुक्त राष्ट्र के 'सम्मेलन एजेंडा' में 'भारत में दलितों के साथ व्यवहार' को शामिल करने पर मतभेद किया था। आपातकाल के दौरान एक बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने हिरासत में रखने के 'राज्य के अप्रतिबंधित अधिकारों के अधिकार' के पक्ष में फैसला सुनाया, न्यायमूर्ति एच आर खन्ना ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में कहा कि, "असहमति कानून की भावना, भविष्य के दिन की बुद्धिमत्ता के लिए एक अपील है, जब बाद में निर्णय त्रुटि को ठीक करने के लिए संभव हो सकता है।" उनके फैसले ने प्रतिष्ठित मुख्य न्यायाधीश की पदोन्नति से इनकार करके उन्हें 'बुरी कीमत चुकानी पड़ी'। 24 साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उसका श्आपातकाल समयश का निर्णय षलत और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वालाष था। मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए न्यायमूर्ति खन्ना की असहमति को हमेशा याद किया जाएगा। असहमति का यही मूल्य और सुंदरता है! आईएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल के एक श्ट्वीटश ने कुछ व्यक्तियों और संगठनों की ओर से श्बुलडोजिंग विरोधश को अप्रिय रूप से जन्म दिया, जिसमें उनसे फिर से यूपीएससी परीक्षा में बैठने और अपने अंकों को बेहतर करने की मांग जैसी अव्यवहारिक चुनौतियाँ शामिल थीं। इसी तरह, कई लोगों ने स्मिता के तर्क का समर्थन किया। उनके विचार में, आईएएस एक श्नेतृत्व की भूमिकाश है, जिसमें कानून और व्यवस्था की स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, चुस्त होना, व्यापक रूप से दौरा करने में सक्षम होना, क्षेत्र का काम करना, मुद्दों को सीधे सुनना और आपदा प्रबंधन के लिए पहला उत्तरदाता होना चाहिए। बाधाओं के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों के प्रति उचित सम्मान के साथ, स्मिता ईमानदारी से महसूस करती हैं कि किसी भी प्रकार की दृश्य, श्रवण, श्लोकोमोटिव विकलांगताश इन कार्यों में बाधा डाल सकती है, जैसे कि विशेष आवश्यकताओं वाली नौकरियों में। यह बात मायने नहीं रखती कि स्मिता पूरी तरह से या आंशिक रूप से सही या गलत हैं, लेकिन क्या उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतभेद और असहमति, जो संविधान के अनुच्छेद 19 और इसकी प्रस्तावना के पीछे का दर्शन है – जिसमें सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का गंभीर संकल्प लिया गया है – को पूरी तरह से नकार दिया जाना चाहिए? भारत में, कुछ समुदायों पर किए गए उत्पीड़न, असमानता और भेदभाव को ठीक करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता थी, जब पहले के समय में हिंदू समाज चार वर्णों या वर्गों में विभाजित था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों को श्सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसानश हुआ और श्अछूतश (दलित), जैसा कि उन्हें तब कहा जाता था, इस व्यवस्था से बाहर हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, नेहरू, अंबेडकर, गांधी आदि जैसे नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत दलितों की मदद करने के प्रयास किए। जब 1882 में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा (विलियम) हंटर आयोग नियुक्त किया गया, तो ज्योति राव फुले और हंटर ने 'जाति–आधारित आरक्षण प्रणाली' का विचार बनाया। बाद में, ब्रिटिश राज ने भारत सरकार अधिनियम 1909 में 'आरक्षण के तत्व' पेश किए। आज जो 'आरक्षण प्रणाली' मौजूद है, उसे 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा 'सांप्रदायिक पुरस्कार' के माध्यम से पेश किया गया था, जिसमें मुसलमानों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो–इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग–अलग प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। गांधी और अंबेडकर के बीच हस्ताक्षरित 'पूना पैक्ट' ने आरक्षण के साथ एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की, जिसमें 'दलितों' के लिए सीटें आरक्षित थीं। तब 'दलित वर्गों' का प्रतिनिधित्व 'अस्थायी' होने का इरादा था। दलित वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, और 'अनुसूचित जाति' शब्द की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, अंबेडकर ने विधान सीटों से लेकर 'सरकारी नौकरियों और शिक्षा' तक आरक्षण के दायरे को सफलतापूर्वक बढ़ाया। मई 1946 के कैबिनेट मिशन वक्तव्य ने संविधान सभा की संरचना के लिए एक योजना बनाई, ताकि निकाय व्यापक आधार वाला हो। मुसलमानों और सिखों के लिए विभाजन के अलावा, इसमें 'सामान्य श्रेणी' का सुझाव दिया गया जिसमें हिंदू, एंग्लो–इंडियन, पारसी, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाएं शामिल होंगी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 'धर्मनिरपेक्ष भारत' बनाने की मांग की थी, ने अंबेडकर को कानून मंत्री नियुक्त किया, जो भारत के संविधान के लिए 'मसौदा समिति' के अध्यक्ष बने। मसौदे में विधानमंडलों में आरक्षण के लाभार्थियों में मुसलमान और भारतीय ईसाई शामिल थे। 1950 में संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया, जो शुरू में क्रमशः 12.5ः घ्और 5ः था, जो अब जनसंख्या में वृद्धि को दर्शाते हुए क्रमशः 15ः और 7.5ः है। मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद, 1990 में, वीपी सिंह सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27ः आरक्षण प्रदान किया। सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10ः आरक्षण 2019 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) अधिनियम ने 1995 में दिव्यांग व्यक्तियों को 3ः आरक्षण प्रदान किया और इसे बढ़ाकर 10ः कर दिया।

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद – केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्द बनाए रखना जरूरी

मनीषा

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद का संघर्ष भारतीय राजनीति में नया नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादा उभर रहा है। हाल के दो मामलों में देखें, तो यह कुछ स्पष्ट होगा। 27 जुलाई को हुई नीति आयोग की बैठक में गैर– भाजपा शासित राज्यों के करीब दस मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। इंडिया गठबंधन से अलग होकर सं ममता बनर्जी जरूर इसमें शामिल हुईं, लेकिन वह भी यह आरोप लगाकर बाहर निकल गईं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें नियमानुसार बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। साथ ही बारी से पहले बोलने के उनके आग्रह को भी स्वीकारा गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया। ममता के बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकलने का राजनीतिक नतीजा यह हुआ कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा सेट किया कि राज्यों के कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख प्रशासन के वह कैसे वाहक बनेंगे, इस पर कोई विशेष चर्चा जनता के बीच नहीं हुई। सिर्फ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मामले बनाम केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति ही सुर्खियां बनीं। दूसरा मामला, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए। इस बयान को भी ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वह बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। इससे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आग–बबूला हो सकते हैं। निशिकांत के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी सांसद के अलावा अन्य किसी जिम्मेदार पद पर नहीं हैं। लेकिन राजनीति में तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। विपक्ष पहले से ही इस बात को लेकर हमलावर है कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। इस बयान को आधार बनाकर विपक्षी नेता आगामी कुछ महीनों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की खबरें भी राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनती रही हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों के राज्यपालों से टकराव तो अदालतों तक पहुंच चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संसद में विपक्ष के मजबूत होने से संघवाद बनाम क्षेत्रवाद की लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव में एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा प्रभावशाली थी, तो दूसरी तरफ उसके विरोध में कई प्रांतों में क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए। यानी प्रतिस्पर्धा द्विदलीय न होकर भाजपा बनाम क्षेत्रवाद बन गई। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में द्रमुक ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच टकराव था। यहां तक कि राज्यपाल ने राज्य के संयुक्त विधानसभा सत्र की बैठक में अभिभाषण (जो राज्य सरकार द्वारा लिखित एवं अनुमोदित होता है) पढ़ने से इन्कार कर दिया था। ऐसा ही कुछ केरल में भी हुआ। यहां राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान एवं वामपंथी गठबंधन के मुख्यमंत्री पी विजयन के बीच सर्वाधिक मतभेद विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर हुआ। कहने का मतलब कि हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बहसबाजी हुई और राज्य सरकारों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कानूनी मसले थोड़े क्लिष्ट हैं, किंतु इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में यह लड़ाई राजनीतिक है। इस राजनीतिक दंगल का सबसे बड़ा प्रतिरूप पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा से जमकर लोहा ले रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़ी मुहिम चलाई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव अभियान की बागडोर अपने हाथों में रखी। लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला अस्मिता के नाम पर क्षेत्रवाद का झंडा बुलंद कर फिर से सत्ता में लौट आईं। अब तक माना जाता रहा है कि राज्यों के चुनाव में ही स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीयता हावी रही। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता ने स्पष्ट किया कि भारत राज्यों की संघीय व्यवस्था है। पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस न्यायालय के सहयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा पाए हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह गुहार लगाई है कि विधान सभा द्वारा पारित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय से लटकाए रखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला भी अधर में लटका हुआ है। न्यायालय ने राज्यपाल कार्यालय और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। राज्यपाल इन आरोपों का खंडन करते हैं। कुल मिलाकर मामला भले ही न्यायालय में लड़ा जा रहा हो, पर यह वास्तव में केंद्र बनाम राज्य तथा संघवाद के ऊपर छिड़ी सघन राजनीतिक लड़ाई है। संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्तियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) का बंटवारा किया गया है। फिर भी केंद्र और राज्यों के बीच हितों और शक्तियों के उपयोग को लेकर समय–समय पर टकराव देखे जाते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक गुलेल चलाने से संघीय प्रणाली नहीं बदलने वाली है। नीति आयोग की बैठक में गैर–भाजपा मुख्यमंत्रियों का हिस्सा न लेना, ममता बनर्जी का बैठक छोड़कर बाहर आना, निशिकांत दुबे के बयान को तूल देना यह सब राजनीतिक तिकड़मबाजी है।

संघर्षों के बल पर ही उपलब्धियां हासिल की है - ध्रुव त्रिपाठी

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। गोरखपुर/ फैजाबाद – शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी के मंगलवार को अयोध्या पहुंचने पर माध्यमिक शिक्षक संघ के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिक्षक विधायक ने जिले के शिक्षक नेताओं के साथ बैठक करके जिले की शिक्षकों की समस्याओं को भी सुना तथा उनके निस्तारण का आश्वासन भी शिक्षक नेताओं को दिया। माध्यमिक शिक्षक संघ जिला मंत्री आलोक तिवारी तथा माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी के नेतृत्व में शिक्षकों ने शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी का फूल माला पहनकर तथा गुलदस्ता भेंट कर जोर दार स्वागत किया।शिक्षक विधायक श्री त्रिपाठी ने इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता में बताया की शिक्षक संगठन ने जो भी प्राप्त किया है अपने संघर्षों के बल पर प्राप्त किया है और आगे भी संघर्षों के बल पर ही वह अपनी उपलब्धियां को प्राप्त करेगा। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है मजदूर नहीं है किंतु वर्तमान सरकार शिक्षकों के साथ बधुवा मजदूर जैसा व्यवहार करने पर तुली है जिसे शिक्षक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पुरानी पेंशन , निशुल्क चिकित्सा लाभ , तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, 28 मार्च 2005 के बाद के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ का विकल्प तत्काल भरवाकर पुरानी पेंशन दिए जाने , एनपीएस की व्यवस्था को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने तथा वित्तविहीन शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने समेत 23 मांगों को ऐसी मांग बताया जिसको शिक्षकों को मिलना ही चाहिए। श्री त्रिपाठी ने कहा कि हम हम अपनी हर मांग को अपने संघर्षों के बल पर लेने के लिए तैयार हैं यदि वर्तमान सरकार हमारी उपलब्धियां को छीनने की कोशिश करेगी तो आने वाले चुनाव में सत्ता से दूर हो जाएगी। संगठन ने अभी अपनी तेज मांगों को लेकर हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया है तथा आगामी 9 अगस्त को हर जिले में मोटरसाइकिल रैली भी निकल जाएगी तथा जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा। संगठन सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष के लिए तैयार है। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार तिवारी,प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवकुमार मिश्र,महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे ,राधेश्याम वर्मा, हरिनारायण ओझा, सत्य प्रकाश, नंदलाल यादव सहित बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।

किन्नर समिति के एक वर्ष सफलतम पूर्ण होने के साथ धूमधाम से मनाया गया हरियाली तीज

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। हरियाली तीज के अवसर पर अतुल्य वेल्फेयर ट्रस्ट परिवार द्वारा हरियाली तीज के साथ गुलाबी समिति के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शहर के एक लॉन में आयोजित किया गया,कार्यक्रम की शुरुआत भगवान शिव पार्वती जी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना मुख्य अतिथि डॉ स्वाति यादव, डॉ शैली निगम, डॉ अंजू कन्नौजिया, पद्मिनी सिंह, राधिका सिंह के साथ डॉ आलोक यादव द्वारा किया गया ,! अपनी संस्कृति और परंपरा को देखते हुए सभी सुहागन औरतें एकत्रित होकर भोले बाबा के गीत गाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए मनाया गया जहां पर सभी सुहागन स्त्रियों ने हरे रंग का वस्त्र धारण कर अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजन किया, ट्रस्ट द्वारा सभी महिलाओं को पान खिला कर पुरानी परंपरा निभाया गया, महिलाओं ने बहुत सारे खेल का भी लुफ्त उठायी! वहीं इस बार हरियाली तीज का पर्व इसलिए और भी अलग दिखाई दिया क्योंकि ट्रस्ट परिवार की महिलाओं के साथ किन्नर समाज गुलाबी समिति कि अध्यक्ष बिट्टू किन्नर और ड़ाली जोशी के द्वारा ट्रस्ट परिवार मे जुड़ने के प्रथम वर्ष सफलतम पूर्ण होने पर केक काटकर सुहागिनों के साथ कार्यक्रम में सम्मिलित कर चार चांद लगा दिया! वहीं ट्रस्ट परिवार ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाली सभी सुहागिन महिलाओं को आशीर्वाद के साथ सुहाग मे सिंदूर, बिंदी मेहंदी और चूड़ियों के साथ अन्य श्रृंगार का समान भी दिया गया ! कार्यक्रम में मुख्य रूप से कंचन सिंह,डॉ अंजू कन्नौजिया, डॉ शकुंतला, डॉ एकता, डॉ प्रीति, डॉ माया, डॉ अलकेशवरी पूनम जायसवाल, मीरा अग्रहरी, ज्योति श्रीवास्तव, मीना गुप्ता, सरोज गुप्ता, पिंकी मौर्या, अनु स्मृति, रीता, जायसवाल,सरोज सिंह महिला थानाध्यक्ष शहर की बहुत सारी सामाजिक राजनीतिक, शिक्षक, डॉक्टर और व्यापारी वर्ग के महिलाओ के साथ बहुत सारी किन्नर समाज के लोग उपस्थित रहे।

बीएसए में परिषदीय विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शासन की मंशानुरूप बेसिक शिक्षा विभाग में गुणवत्ता संवर्धन एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल ने मंगलवार को विकास क्षेत्र करंजाकला एवं शाहगंज के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गय बीएसए द्वारा सर्वप्रथम विकास खण्ड करंजाकला के प्राथमिक विद्यालय काफरपुर का निरीक्षण किया। विद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित कुल 101 छात्रों के सापेक्ष 80 छात्र उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित छात्रों के सापेक्ष 85 छात्रों की डीबीटी विद्यालय द्वारा की गयी जाँच मे पायी गयी। विद्यालय को प्राप्त कंवर्जन धनराशि 50000 के सापेक्ष आय–व्यय पंजिका प्राधानाध्यापक श्री प्रसन्न कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी। गत वर्ष व्यय धनराशि के बिल–बाउचर विद्यालय मे उपलब्ध नहीं पाये गये। विद्यालय प्रांगण गन्दा एवं बाउंड्रीवाल रंगाई–पुताई विहीन पाया गया। विद्यालय मे अवस्थित कुल कक्षा–कक्षों के सापेक्ष सिर्फ 2 कक्षा–कक्ष की रंगाई–पुताई प्राप्त होने पर बीएसए द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये सम्बंधित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

तत्पश्चात विकासखण्ड शाहगंज के प्राथमिक विद्यालय अतरहीं का निरीक्षण किया गया। विद्यालय मे कार्यरत सहायक अध्यापक श्री अमित कुमार एवं सहायक अध्यापिका श्रीमती नीलू सिंह अध्यापक उपस्थित पंजिका मे हस्ताक्षर कर विद्यालय पर अनधिकृत रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थिति पाये गये। जिसके कारण बीएसए द्वारा दोनों शिक्षक एवं शिक्षिका का अग्रिम आदेश तक वेतन अवरूद्ध करते हुये स्पष्टीकरण निर्गत किया गया। विद्यालय मे कार्यरत शेष समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित कुल 69 छात्रों के सापेक्ष 45 छात्र उपस्थित मिले। विद्यालय

को प्राप्त कंवर्जन धनराशि 50000 के सापेक्ष आय–व्यय पंजिका प्रधानाध्यापक श्री रजीत कुमार द्वारा अवलोकित नहीं करायी जा सकी। प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत विद्यालय मे दाल–चावल बना हुआ पाया गया। विद्यालय की रंगाई–पुताई की गयी पायी गयी, परन्तु विद्यालय की छत पर पौधे उगे हुये दृष्टिगत हुये। जिसके कारण बीएसए द्वारा सम्बंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह में विद्यालय मे प्राप्त कमियों को दूर करते हुये साक्ष्य सहित सपष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कम्पोजिट विद्यालय खलीलपुर का निरीक्षण बीएसए द्वारा अपरान्ह 01रू25 पर किया गया। विद्यालय मे कार्यरत सहायक अध्यापिका श्रीमती जागृती सिंह एवं शिक्षा मित्र श्रीमती नीलम सिंह अवकाश पर पायी गयी। विद्यालय मे कार्यरत शेष समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित कुल 309 छात्रों के सापेक्ष 232 छात्र उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित छात्रों के सापेक्ष 298 छात्रों की डीबीटी विद्यालय द्वारा की गयी जाँच मे पायी गयी। विद्यालय को प्राप्त कंवर्जन धनराशि 75000 के सापेक्ष आय–व्यय पंजिका सम्बंधित प्रधानाध्यापक द्वारा अवलोकित नहीं करायी जा सकी। विद्यालय की रंगाई–पुताई परिसर के सिर्फ एक तरफ करायी गयी पायी गयी। जिसके कारण बीएसए द्वारा सम्बंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह में विद्यालय मे प्राप्त कमियों को दूर करते हुये साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कम्पोजिट विद्यालय कैसरपुर अदाई का निरीक्षण किया गया। विद्यालय मे कार्यरत सहायक अध्यापक श्री जंगबहादुर यादव अध्यापक उपस्थित पंजिका मे हस्ताक्षर कर विद्यालय पर अनधिकृत रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थिति पाये गये। जिसके कारण बीएसए द्वारा शिक्षक का अग्रिम आदेश तक वेतन अवरूद्ध करते हुये स्पष्टीकरण निर्गत किया गया। विद्यालय मे कार्यरत शेष समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालय उपस्थित मिले। विद्यालय मे नामांकित कुल 70 छात्रों के सापेक्ष 52 छात्र उपस्थित मिले। विद्यालय को प्राप्त कंवर्जन धनराशि 25000 के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि प्रधानाध्यापक द्वारा खर्च की गयी प्राप्त हुयी। विद्यालय की रंगाई–पुताई नहीं की गयी प्राप्त हुयी, जिसके सम्बंध में बीएसए द्वारा पूछे जाने पर सम्बंधित प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा विद्यालय हेतु आलमारी एवं कुर्सी–मेज उक्त धनराशि से क्रय की गयी है। जिसके कारण बीएसए द्वारा सम्बंधित प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह में विद्यालय मे प्राप्त कमियों को दूर करते हुये साक्ष्य सहित सपष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

फीनिक्स पलासियो में आयोजित हुई रोमांटिक ख्यालों की एक शाम, एन इवनिंग विद रविंदर

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। फीनिक्स पलासियो, लखनऊ ने अपने लग्जरी रेस्टोरेंट एट में , एन इवनिंग विद रविंदर का आयोजन किया। इस इवेंट में मशहूर रोमांस लेखक रविंदर सिंह शामिल हुए, जिन्होंने अपने प्यार और दिल टूटने की कहानियों को उपस्थित दर्शकों के साथ साझा किया। 11 बेस्टसेलर और 3.5 मिलियन से अधिक प्रतियों की बिक्री के साथ, रविंदर सिंह रिश्तों की नब्ज समझने और पकड़ने में माहिर हैं। उनका यही हुनर उन्हें साहित्यिक दुनिया में सबकी पसंदीदा शख्सियत बनाता है। रविंदर सिंह की उपस्थिति शुक्रवार शाम का मुख्य आकर्षण थी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत किस्सों और काम की झलकियां पेश करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इंसानों की सबसे शक्तिशाली भावना – प्यार – पर चर्चा करने के लिए मेहमानों को आमंत्रित भी किया। एट के शांत और रोमांटिक माहौल ने इन गहन चर्चाओं को यादगार बना दिया। जैसे–जैसे उपस्थित मेहमान रविंदर सिंह की शब्दों की दुनिया में डूबते गए, एट का माहौल जादू को और बढ़ाता गया। रेस्टोरेंट के माहौल और लजीज व्यंजनों ने शाम की थीम में स्वाद का तड़का लगाया। फीनिक्स मिल्स के सीनियर सेंटर डायरेक्टर, श्री संजीव सरीन ने इस आयोजन की सफलता पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, ष्फीनिक्स पलासियो में रविंदर सिंह की मेजबानी करना हमारे लिए एक सम्मान की बात थी। एट का अनोखा माहौल शाम के मूड के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था, जिससे मेहमान दिलचस्प बातचीत की गहराइयों में खुद को पूरी तरह खो बैठे। हम बेहतरीन अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और यह इवेंट इसका एक शानदार उदाहरण था।

समाजसेवी जज सिंह अन्ना ने मुख्यमंत्री के संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी का सौंपा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। शारदा सहायक खण्ड 39 नहर में पानी न आने से समाजसेवी जज सिंह अन्ना ने मंगलवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समाजसेवी जज सिंह अन्ना ने बताया कि 25 जुलाई को आमरण अनशन करने एवं जिलाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों के सख्त निर्देश पर शारदा सहायक खण्ड 39 नहर विभाग के अधिकारियों ने नहर में पानी छोड़ा जो कराही में तेल के समान था। जो मीरगंज क्षेत्र में पानी नही पहुंचा। जनरेटर से भी पानी खींचने पर नहर में पानी सूख जा रहा है। यह नहर के विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही अनदेखी, गैर जिम्मेदाराना कही जाएगी, जबकि मड़ियाहूं , बाबतपुर नहर में फूल पानी तीव्र गति से आ रहा है। मुंगराबादशाहपुर ,मछलीशहर में धान की रोपाई किसी भी खेत में नही हो पा रही है। गत वर्ष भी शारदा सहायक खण्ड 39 नहर और मछलीशहर रजवाहा में पानी नही आया था।वही एक ही जिलें में एक शारदा खण्ड 39 नहर में पानी नही आ रहा है । वही दूसरे मड़ियाहूं बाबतपुर नहर में फूल पानी सप्लाई हो रही है। यह दो आंखों की मिचौली सरकार द्वारा क्यो की जा रही है। शारदा सहायक खण्ड 39 नहर में एक लापरवाह अधिकारी जो कभी कार्य क्षेत्र पर नही जाता है।नहर विभाग के एसडीओ जो 8 वर्षो से अपने एक ही पद पर एक ही जगह ड्यूटी कर रहे है। किसान इनसे नाराज हो चुके है इनका स्थांतरण करने की मांग करते है।

डीएम ने संजय कुमार अग्रहरि को बनाया तहसील सवायजपुर का नया उपजिलाधिकारी'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली(हरदोई)' जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने तहसील सदर में रहे तहसीलदार संजय कुमार अग्रहरि को तहसील सवायजपुर का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया है। नवागत उपजिलाधिकारी ने रविवार को तहसील पहुँच कर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। आपको बता दें कि तहसील सवायजपुर एसडीएम धीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का तबादला नगर मजिस्ट्रेट रायबरेली के पद पर हो गया। जिसके बाद डीएम ने संजय कुमार अग्रहरि को तहसील सवायजपुर का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया है। संजय कुमार अग्रहरि ने तहसील मुख्यालय पहुंच कर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि शासन की मंशानुरूप वह प्रतिदिन अपने कार्यालय में बैठकर जन समस्याओं को सुनकर पीड़ितों को न्याय दिलाना और फरियादियों की समस्याओं का निराकरण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जिससे कोई फरियादी उनके यहाँ से निराश होकर न जाये।उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जायेंगे और सरकारी जमीनों को

भू–माफियाओं से कब्जा मुक्त कराया जायेगा। इसके लिए राजस्व की टीम गठित कर अभियान चलाया जायेगा। मंगलवार को उपजिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मियों एवं अधिवक्ताओं के साथ तहसील सभागार में बैठक कर राजस्व से सम्बंधित तहसील स्तर पर एवं क्षेत्र में आने वाली समस्याओं एवं उसके निराकरण को लेकर चर्चा की। बैठक में उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि तहसील स्तर से सभी को न्याय मिलेगा साथ ही पीड़ित की हर सम्भव मदद की जायेगी।

रिश्वतखोर दरोगा को 10 हजार रुपए रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। बदलापुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम का

हफ्ते भर के अंदर में यह दूसरी बार किसी अधिकारी को रिश्वतखोरी में उठाया गया।जो जिले भर में चर्चा का विषय बना हुआ है घटना पुलिस विभाग की है। तेजीबाजार थाने के दरोगा हैदर अली को मंगलवार को दस हजार रूपये जेसीबी मालिक से रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम ने रंगें हाथ पकडकर बदलापुर थाने ले आकर कार्यवाही की।तेजीबाजार थाना क्षेत्र के आशुतोष यादव बरियार गांव को जेसीबी छुडाने के नाम पर दरोगा हैदर अली रिश्वत मांग रहे थे। रिस्वत न देने पर जेसीबी जप्त कर देने की धमकी भी दे रहे थे। जिसके बाद पिड़ित आशुतोष यादव एंटी करप्शन टीम नीरज सिंह से मिले और मंगलवार को दस हजार रुपए नहर पर देते ही दरोगा हैदर अली को टीम ने उठाया ऐसे में दरोगा हैदर अली भागने का प्रयास किया। जिस पर टीम ने पकड़ कर बदलापुर थाने ले आकर कार्यवाही करते हुए साथ ले गई। इस मामले में बात करते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम के निरक्षक नीरज सिंह ने बताया की बरियार गांव निवासी आशुतोष यादव ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन टीम वाराणसी को सूचना दिया कि वह तेजी बाजार थाने पर तैनात उप निरीक्षक हैदर अली को अपनी जेसीबी छुड़ाने के लिए 10 हजार रुपये घूस देगा। इस सूचना पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी से निरीक्षक नीरज सिंह के नेतृत्व में टीम मंगलवार को तेजी बाजार थाना क्षेत्र में आई और आशुतोष यादव द्वारा उप निरीक्षक हैदर अली को 10 हजार रुपये देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात टीम द्वारा उप निरीक्षक को बदलापुर थाने पर लाया गया जहां पर मुकदमा दर्ज कराकर उसे वाराणसी ले जाया गया। भ्रष्टाचार निवारण संगठन की टीम कल बुधवार 07 अगस्त को पकड़े गए उप निरीक्षक को भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के समक्ष वाराणसी में पेश करेगी। विदित हो कि इसके 3 वर्ष पहले यही उप निरीक्षक जिले के सुरेरी थाने पर तैनात रहा और वहां पर भी मुकदमे में चार्जशीट लगाने के नाम पर 10 हजार रुपये लेते गिरफ्तार हुए थे और काफी दिनों तक जेल में रहे,जेल से छूटने के बाद इन्हें तेजी बाजार थाने पर तैनात कर दिया गया जहां पर यह दोबारा पकड़े गए।

आल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे में विजई होकर किया जिले का नाम रोशन

अयोध्या। दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम मे आयोजित ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस कप कराटे चौंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता प्रतिभाग करने जिले के अंकुर विजय मार्शल आर्ट अकादमी से कुछ बच्चे गये थे।जहां पर इस प्रतियोगिता में इस अकादमी से व उदया पब्लिक स्कूल में कक्षा सात में पढ़ने वाले छात्र शौर्य चौधरी भी दिल्ली गये थे। इस प्रतियोगिता में अंकुर विजय मार्शल आर्ट अकादमी अयोध्या के प्रतिभागी अंशिका श्रीवास्तव एवं शौर्य चौधरी 42 किलोग्राम भार वर्ग भार वर्ग में एवं शौर्य चौधरी ने– 40 किलोग्राम भार वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। इन विजयी खिलाड़ियों के अयोध्या आगमन पर रेलवे स्टेशन पर संस्था के अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव एवं तपन चौधरी सहित अन्य लोगों ने विजेताओं को माला पहनाकर उनका स्वागत किया।

कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने एक दर्जन कर्मियों का रोका वेतन

अयोध्या। अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के चलते जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने मया बाजार में तैनात दो सुपरवाइजर व तारुन विकास खण्ड में तैनात एक सुपरवाइजर का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये है।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि मया बाजार में सुपरवाइजर के पद पर तैनात दोनों सुपरवाइजर ऊषा वर्मा व माला वर्मा के साथ साथ तारुन

विकास खण्ड में तैनात सुपरवाइजर शकुन्तला दूबे को आठ माह से अपने कार्यशैली में सुधार लाने को कहा जा रहा है।इसके लिए उन्हें कई बार मौखिक रुप से अपने कार्यो के लापरवाही न बरतने के लिए समझाया गया।लेकिन कोई सुधार न होने के चलते उन्हें नोटिस जारी करते हुए अगले आदेश तक इन तीनों सुपरवाइजरो का वेतन तत्काल प्रभाव से रोका गया है।इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में लापरवाही बरतने के चलते पूरा व अमानीगंज में तैनात आठ कर्मियों का जिसमें सुपरवाइजर व लिपिको का जुलाई माह का वेतन रोकने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये है।

रघु राय की फोटो पत्रकारिता पर अमित मिश्रा की हुई शोध मौखिकी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग के शोधार्थी अमित मिश्रा की पीएच.डी. मौखिकी का आयोजन मंगलवार को हुआ। शोध का विषय सामाजिक यथार्थ का प्रस्तुतीकरण और समकालीन फोटो पत्रकारिता (रघु राय की फोटो पत्रकारिता के विशेष संदर्भ में) है। यह शोध जनसंचार विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार के निर्देशन में पूरा हुआ है। इस शोध के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक यथार्थ की वास्तविकता को रघुराय की फोटोग्राफी के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया है। शोधार्थी ने अपने शोध में रघुराय की तस्वीरों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि कैसे रघु राय की फोटो पत्रकारिता ने समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों को

उजागर किया है। उन्होंने अपने शोध में रघुराय की फोटोग्राफी के तरीकों और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया और यह बताया कि कैसे ये तस्वीरें समाज की वास्तविकता को समझने और उसे व्यापक जनता के सामने प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाह्य विशेषज्ञ के रूप में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. अनिल कुमार उपाध्याय थे। मौखिकी के दौरान विशेषज्ञों ने अमित मिश्रा के शोध की सराहना की और उनके द्वारा किए गए कार्य की गहनता और सटीकता की प्रशंसा की। साथ ही कहा कि यह शोध न केवल फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है, बल्कि यह समाजशास्त्र और मीडिया अध्ययन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस अवसर पर वाह्य परीक्षक प्रो. अनिल कुमार उपाध्याय, प्रो. मनोज मिश्र, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. दिग्विजय सिंह राठौर, डॉ चंदन सिंह समेत विभाग के सभी लोग शामिल थे।

'इसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने किया सरेंडर, रिहा

सुलतानपुर। कोतवाली नगर के पांचोपीरन निवासी इसौली विधानसभा क्षेत्र के सपा विधायक मोहम्मद ताहिर खान ने एमपी–एमएलए की विशेष कोर्ट में सोमवार को सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया गया।विधायक के अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने विधायक की जमानत अर्जी पेश कर कहा कि मामला राजनीतिक द्वेष में गलत तरीके से दर्ज कराया गया,जिसका कोई साक्ष्य अभियोजन के पास मौजूद नहीं है। मोहम्मद ताहिर खान वर्तमान समय में इसौली विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं।जिनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है।

कोर्ट ने अधिवक्ता के तर्कों और साक्ष्य के आधार पर विधायक की जमानत मंजूर कर कोर्ट से रिहा कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख नियत की है।विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडेय के मुताबिक विधायक मोहम्मद ताहिर खान पर तत्कालीन प्रभारी अधिकारी वन विभाग के दरोगा मुकेश कुमार ने 3 फरवरी 2000 की घटना में वन विभाग अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। आरोप है कि आरक्षित वन कब्जा कर राजस्थानी ट्रैक्टर से वन कब्जा कर सड़क निर्माण कर रहे थे। मना करने पर अपमानित किया। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट ने इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान को सम्मन जारी कर तलब किया था।

सहायक श्रम मधुसूदन राम आयुक्त को व्यापारियों ने ज्ञापन दिया

सुल्तानपुर। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रवींद्र ने मांग पत्र के माध्यम से कहा कि जनपद सुल्तानपुर की बाजारों में व्यापारीयों के द्वारा उठाई गई समस्यायों की दृष्टि गत मांग पत्र दिया जा रहा है यथा शीघ्र कार्यवा ही करने की कृपा करें।

1–श्रम विभाग के द्वारा पंजीयन के लिए तहसील स्तरीय शिविर लगाकर पंजीयन कराया जाए।

2–कारखाना पंजीयन के संदर्भ अभी जनपद के उद्यमियों को जानकारी नहीं है पूर्व में आपसे बात हुई थी कि आप द्वारा अपने विभाग कार्यालय में एक व्यक्ति को बैठाएंगे जो कारखाना पंजीयन के लिए लोगों को जानकारी दे। जिसका पालन नहीं हो रहा है।

3–जांच करने के पहले उद्यमियों व्यापारियों को नियम कानून की जानकारी दीजिए उसके बाद किसी व्यापारी को नोटिस दी जाए या कार्यवाही की जाए किसी भी दशा में व्यापारी उद्यमी का उत्पीड़न ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाए।

4–जनपद में तहसील स्तरीय जागरूकता अभियान चलाया जाए जागरूकता अभियान के दौरान सभी श्रम विभाग के नियम व कानून उद्यमियों पर व्यापारियों को समझाया जाए।

5–जो भी अधिकारी व्यापारियों को प्रतिष्ठान पर जाए वह अपना परिचय पत्र अपने गले में पहनें रहे,अपने साथ किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को लेकर या अपने प्राइवेट ड्राइवर को लेकर व्यापारियों के प्रतिष्ठान पर न जाएं और प्रथम दृष्टया व्यापारियों व उद्यमियों को सचेत करें यदि उसके बाद भी पालन न हो तब कार्यवाही करें।

मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में 1284 मरीजों को मिला उपचार

शामली, संवाददाता। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया। आरोग्य मेले में नजला, खांसी और बुखार के मरीज आए। इस दौरान 1284 मरीजों की जांच कर उपचार दिया गया। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के 62 गोल्डन कार्ड बनाए गए। रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों की जांच की। जिले के सभी 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित हुआ। शहर के मोहल्ला बरखंडी स्थित अरबन पीएचसी में पर डॉ. उदित भटनागर ने मरीजों की जांच कर दवा दी। इस दौरान 49 मरीजों को उपचार दिया गया। मोहल्ला पंसारियान स्थित अरबन पीएचसी पर 53 मरीजों की जांच कर उपचार दिया गया। आरोग्य मेले में डॉ. सादिया सदफ ने मरीजों की जांच कर दवा दी गई। आरोग्य मेलों में 371 पुरुष, 596 महिला और 317 बच्चों कुल 1284 मरीजों को उपचार दिया गया। चिकित्सकों ने बताया आरोग्य मेले में नजला, खांसी और बुखार के मरीज ज्यादा आए। इसके अलावा त्वचा व पेट संबंधी मरीज भी पहुंचे। इस दौरान आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के 62 गोल्डन कार्ड बनाए गए।

हैलट में खुलेगा बर्न व प्लास्टिक सर्जरी का 50 बेड का नया विभाग

कानपुर, संवाददाता। हैलट में बर्न व प्लास्टिक सर्जरी का नया विभाग खुलेगा। इससे जलने के रोगियों को बहुत राहत मिलेगी। विभाग इसी साल से चालू हो जाएगा। विभाग में विशेषज्ञों की सुविधाओं के साथ ही बर्न के रोगियों को इंटेसिव केयर की भी सुविधा मिलेगी। रोगियों को इलाज के लिए लखनऊ, दिल्ली इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज प्रबंधन शासन को बर्न वार्ड को विभाग में तब्दील करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला का कहना है कि सिविल कार्य 90 फीसदी हो चुका है। विभाग इसी वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। हैलट में उच्चीकृत बर्न वार्ड के लिए शासन पहले ही मंजूरी दे चुका है। इसके साथ ही आईसीयू के बेड और वार्ड के बेड बढ़ाने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया है। विभाग के लिए जरूरी दूसरी फैकल्टी और प्रशिक्षित स्टाफ भी मांगा जा रहा है। डॉ. काला का कहना है कि स्टाफ और उपकरण मिलने में छह महीने लग सकते हैं। विभाग के लिए भवन उपलब्ध है। मौजूदा भवन में एक तल और बढ़ा दिया जाएगा। यह प्रशासनिक ब्लॉक रहेगा। रोगियों की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी तथा ऑक्सीजन थैरेपी की भी व्यवस्था रहेगी। इससे बर्न रोगियों के घाव सूखने में आसानी होगी।

डॉ. काला ने बताया कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग अभी किसी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध नहीं है। यह पहला कॉलेज होगा, जिसमें विभाग खुलेगा। हैलट में मंडल के अलावा आसपास के 17 जिलों के बर्न रोगी इलाज के लिए आते हैं। साथ ही विभाग में नए विशेषज्ञ भी तैयार होंगे।

अभी इलाज की क्या है हालत

पूरे मंडल में बर्न वार्ड सिर्फ उर्सला में है। यहां आठ बेड हैं जो छह साल से लगातार भरे रहते हैं।

बर्न रोगियों की संख्या बढ़ने पर एनबी–2 वार्ड में अलग से छह बेड की व्यवस्था कर दी गई है। जैसे ही बर्न वार्ड में कोई बेड खाली होता है, एनबी–2 के वार्ड से रोगी शिफ्ट कर दिया जाता है। गंभीर रोगी को लखनऊ रेफर करना पड़ता है। उर्सला में कोई प्लास्टिक सर्जन नहीं है। सामान्य सर्जन ही बर्न रोगी देखते हैं।

अनंत निधि क्रेडिट सोसाइटी का फरार 25 हजार का इनामी उपनिदेशक गिरफ्तार

कानपुर, संवाददाता। तीन साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी अनंत निधि क्रेडिट सोसाइटी के उपनिदेशक अवनीश बाथम को बिठूर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अवनीश पर 1.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। मामले में पुलिस एक माह पहले निदेशक राजेश कुमार द्विवेदी को जेल भेज चुकी है। बिठूर के बगदौधी बांगर मंधना निवासी शिव सिंह कुशवाहा और कल्याणपुर निवासी अंचल कनौजिया ने बताया कि अनंत निधि क्रेडिट सोसाइटी ने सन 2013 में कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। ऑफिस गुमटी नंबर पांच में था। आरोपियों ने पीड़ितों को भारत सरकार लिखे हुए किसान पत्र और विकास पत्र बेचे थे। साथ ही पांच साल में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 24 से अधिक लोगों से करीब 1.12 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कंपनी 2018 में निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गई थी। बिठूर के मंधना निवासी शिव किशन पाल, आशुतोष कुमार, शिव सिंह, अंचल कनौजिया ने कंपनी के उपनिदेशक अवनीश कुमार बाथम और निदेशक राजेश कुमार द्विवेदी, रितेश श्रीवास्तव, अशोक श्रीवास्तव पर बिठूर थाने में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक दरोगा प्रमोद कुमार ने बताया कि अयोध्या निवासी नीतेश श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। वह नैनी जेल में बंद है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया रविवार को कंपनी के उपनिदेशक बिठूर के हिंदूपुर निवासी अवनीश बाथम को परियर पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस की गाड़ी के सामने आए युवक को सिपाही ने डंडे से पीटा

बिजनौर, संवाददाता। बढ़ापुर के मदपुरी गांव में विवाद निपटाने पहुंची पुलिस ने खुद ही बखेड़ा कर दिया। डायल 112 पीआरवी की गाड़ी के सामने अचानक आकर खड़े हुए एक शराबी युवक पर पुलिस ने खूब गुस्सा उतारा। लोगों की भीड़ के बीच युवक को डंडे से पीटा गया और लात भी मारी। यह देख आक्रोशित लोग दौड़ पड़े। पुलिसकर्मी गाड़ी को लेकर गांव से भाग निकले। अब इस मामले का वीडियो वायरल होने पर एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। शनिवार की देर शाम ग्राम मदपुरी निवासी गोल्डी सिंह का बाइक को लेकर किसी से विवाद हुआ। गोल्डी ने डायल 112 पर फोन कर दिया। शिकायत का निस्तारण कर पुलिस गांव से लौट रही थी। इसी बीच गांव में हरजिंदर सिंह अचानक पुलिस की गाड़ी के आगे आ गया और नशे की हालत में खड़ा हो गया। इस पर सिपाही पंकज सिंह गाड़ी से उतरा और युवक को हटाने का प्रयास किया। सिपाही ने डंडे से युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी। सड़क पर गिरा गिराकर पीटा गया। लात भी मारी। कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों को गुस्से में देख सिपाही गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उधर, ग्रामीणों ने गाड़ी को पकड़ने का प्रयास भी किया। गांव वालों से वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही सीओ से मामले की प्राथमिक जांच कराई गई। प्राथमिक जांच के बाद सिपाही पंकज कुमार को एसपी अभिषेक झा ने निलंबित कर दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

दिल्ली–सहारनपुर एक्सप्रेस के आठ पहिये पटरी से उतरे, दौड़े अफसर

सहारनपुर, संवाददाता। रेलवे स्टेशन पर शारदा नगर पुल के नीचे दिल्ली–सहारनपुर एक्सप्रेस के आठ पहिये बेपटरी हो गए। हादसे का पता लगते ही सहारनपुर से लेकर अंबाला तक अफसरों में खलबली मच गई। इस दौरान दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) को बुलाया गया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पहिए पटरी पर लाए गए। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। सांसद इमरान मसूद भी घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रेन नंबर 01619 दिल्ली–सहारनपुर एक्सप्रेस रविवार को अपने निर्धारित समय से करीब आधे घंटे लेट पहुंची। ट्रेन से यात्री प्लेटफार्म उतरे। इसके बाद लोको पायलट ट्रेन को अंबाला की तरफ बनी वाशिंग लाइन लेकर पहुंचा। दोपहर करीब 12रू55 बजे शारदा नगर पुल के नीचे लाइन पर पीछे करते समय ट्रेन का एक कोच बेटपरी हो गया। ट्रेन के डिरेल होते ही रेलवे स्टेशन के कंट्रोल रूम में जानकारी दी गई। रेल अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। साथ ही दुर्घटना राहत ट्रेन (एआरटी) को भी रवाना किया गया। टीम ने राहत कार्य शुरू करते हुए शाम करीब पांच बजे पटरी से उतरे पहियों को वापस पटरी पर ला दिया। हालांकि, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही ट्रेनों के संचालन पर कोई असर पड़ा।

लगातार हो रहे ट्रेन हादसे, रेलमंत्री थपथपा रहे पीठ

शारदा नगर पुल के नीचे ट्रेन बेपटरी का पता लगते ही सांसद इमरान मसूद मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से घटना की जानकारी ली।

इस दौरान इमरान मसूद ने लगातार हो रहे ट्रेन हादसों पर सरकार को घेरा। कहा कि गनीमत रही कि यहां कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन पूरे देश में ट्रेनें बेपटरी हो रहीं हैं। रेलमंत्री केवल अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अब लोग ट्रेनों में बैठने से भी डरने लगे हैं। पता नहीं कब हादसा हो जाए।

टीम गठित कर दी है, जो जांच करेंगी – डीआरएम

अंबाला मंडल के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि सहारनपुर में शटिंग के दौरान ट्रेन के कुछ पहिए बेपटरी हो गए थे। ट्रेन में कोई यात्री नहीं था। वह खाली थी। अधिकारियों की एक टीम गठित कर दी है, जो पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही रिपोर्ट के आधार पर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

स्पा सेंटर मालिक से रंगदारी मांगने में दो कथित पत्रकार गिरफ्तार हुए

कानपुर, संवाददाता। कानपुर के घंटाघर में स्पा सेंटर मालिक से रंगदारी मांगने के आरोप में दो कथित पत्रकारों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी इलाके की कई दुकानों से वसूली करते हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। चकेरी के गिरजानगर में रहने वाली जिया मलिक ने बताया कि एक्सप्रेस रोड स्थित एक होटल की तीसरी मंजिल पर वह बॉडी मसाज सेंटर चलाती हैं। आरोप है कि दो अगस्त की रात करीब 8:00 बजे खुद को पत्रकार बताने वाले शुभम और नितिन सिंह होटल आए। आरोपियों ने उन्हें नीचे बुलाया और पांच हजार रुपये व बीयर की आठ बोतलें मांगी। वजह पूछने पर आरोपियों ने बताया कि वे पत्रकार हैं। इलाके में ऐसा काम करने वाले सभी महीना देते हैं। धमकी से डरकर जिया ने एक हजार रुपये दिए। आरोप है कि दोनों ने नीचे राहुल नामक व्यक्ति को रुपये वापस कर दिए और 10 हजार रुपये की मांग की।

पीड़ित महिला ने हरबंशमोहाल पुलिस से शिकायत की। एसीपी कलक्टरगंज मोहसिन खान ने बताया जिया मलिक की तहरीर पर वसूली व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है।

मक्खन निकालते समय महिला के पेट में घुसी मथानी, हुई दर्दनाक मौत

अलीगढ़, संवाददाता। जरा सी चूक महिला के लिए मौत की वजह बन गई। अतरौली के गांव शेखूपुर में महिला ने दही मथने वाली मथानी की चटकनी बंद कर दी, पर बोर्ड से प्लग नहीं निकाला। अचानक चटकनी दब गई और मथनी ने महिला का पेट चीर दिया। अधिक खून बहने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जिससे परिवार में मातम छा गया। अतरौली कोतवाली के गांव शेखूपुर निवासी गगन कुमार बिल्डिंग में लिंटर डालने के लिए शटरिंग लगाने का काम मजदूरी पर करते हैं। 5 अगस्त सुबह गगन कुमार काम पर चले गए।

पत्नी ने दही से मट्ठा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मथानी बिजली के बोर्ड से लगाकर दही दोहने के लिए बर्तन में लगा दी। घरेलू काम खत्म करने के बाद करीब 12 बजे वह दही से मक्खन निकालने लगीं। महिला ने मथानी की चटकनी बंद कर दी और बोर्ड से प्लग नहीं निकाला। प्रीति मथानी को गोद में रखकर मक्खन निकाल रही थीं, इसी दौरान मथानी की चटकनी ऑन हो गई और मथानी चल गई। मथानी ने महिला के पेट में छेद कर दिया, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा।

उस वक्त घर में कोई नहीं था। डेढ़ साल का बेटा कुनाल जगा तो वह जोर–जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी महिला उनके घर पहुंची तो वहां खून से लथपथ प्रीति का शव पड़ा देख उसके होश उड़ गए।

महिला रोती चीखती हुई घर से बाहर आई और शोर मचाया। गांव के तमाम लोग वहां पहुंच गए। सूचना मिलने पर पति गगन भी आ गए। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पूर्व जिप सदस्य केपी मिस्त्री, राजू लोधी प्रधान सहित तमाम लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया।

डेढ़ साल की भतीजी को कारोबारी ने कार से रौंदा

मेरठ, संवाददाता। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र के प्रीत विहार में 18 माह की बालिका को कुचलने वाले कार चालक की गिरफ्तारी न होने पर चाचा ने कमिश्नरी पर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पीएसी के जवानों ने किसी तरह पेट्रोल की बोतल छीनकर उसे बचाया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। प्रीत विहार में शनिवार को घर से बाहर खेल रही 18 माह की कनिष्का पुत्री अभिषेक को कार सवार ने कुचल दिया था। बालिका की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजनों ने कार चालक संजय गुप्ता को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध बालिका का चाचा विक्रम सोमवार इसके बाद वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। सिविल लाइन पुलिस

को कमिश्नर ऑफिस के गेट पर पहुंचा। खुद पर पेट्रोल डालकर उसने आत्मदाह का प्रयास किया। तभी पीएसी के जवानों ने उसे रोक दिया। पीड़ित को उठाकर ले गई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

जीजा को लूटने वाला साला गिरफ्तार

बांदा, संवाददाता। साले ने साथी के साथ मिलकर जीजा को लूट लिया। पीड़ित ने मटौंध थाने में सूचना दी तो पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दो घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से सोने की चेन, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र निवासी रामजी ने मटौंध थाने में रविवार को तहरीर दी। बताया कि वह शनिवार की सुबह मोहनपुरवा गांव से जंगल जाने वाले रास्ते से आ रहे थे। यहां उसके साले रामजी और उसके दो साथियों ने तमंचे के बल पर उसे लूट लिया। मटौंध थाने में रविवार को मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दो घंटे के अंदर ही आरोपी साले मुडेरी गांव निवासी रामजी सिंह व उसके साथी मोहनपुरवा निवासी संजय पाल को सेमरिया दाई मंदिर के पास से गिरफ्तार किया है। मटौंध थाना इंस्पेक्टर राममोहन राय ने बताया कि तीसरा आरोपी मोहनपुरवा निवासी प्रांशु यादव भाग निकला है।

घर के बाहर खेल रहा था पांच साल का मासूम, सांप ने डंस लिया

शामली, संवाददाता। ऊन क्षेत्र के गांव मुंडेट खादर में सांप के काटने से पांच वर्षीय बालक की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के चलते उसे शामली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गांव मुंडेर खादर निवासी ऋतिक (5) पुत्र नितिन अपने घर के बाहर खेल रहा था। बताया गया कि तभी काले रंग के सांप ने उसके पैर में काट लिया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. किशोर कुमार आहूजा ने बताया कि बरसात के मौसम में सांप अकसर बिल से बाहर निकल आते हैं। अगर किसी को सांप काट लेता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। झाड़ फूंक व टोना–टोटका आदि के चक्कर में कतई न पड़ें। अस्पताल में समय पर पहुंचकर उपचार कराएं।

कानपुर समेत आसपास के शहरों में दो दिन होगी बूंदाबांदी

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में रविवार को सुबह से ही घने बादलों के बीच करीब 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, लेकिन बारिश नहीं हुई। शहर के कुछ हिस्सो में सिर्फ बूंदाबांदी ही रही। सीएसए मौसम विभाग के अनुसार सात और आठ अगस्त को महानगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। दिन में बादलों छाये रहने की वजह से धूप का असर कम रहा है, जिससे अधिकतम पारा आज के दिन के सामान्य से 0.2 डिग्री कम 32.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जबकि रात का तापमान सामान्य से 3.6 अधिक 26 डिग्री रहा। अभी 5 और 6 अगस्त के बीच बादलों के साथ तेज हवा चल सकती है। इस बीच बूंदाबांदी भी होगी।

बिजली का जर्जर खंभा युवक के सिर पर गिरा, मौत

बांदा, संवाददाता। बाजार से पैदल घर जा रहे युवक के ऊपर बिजली का जर्जर खंभा गिर गया। इससे वह गंभीर घायल हो गया। इलाज के दौरान मौत हो गई। अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर लाई मंडी के पीछे निवासी अंकित कुशवाहा (19) शनिवार की देर शाम बाजार से पैदल घर जा रहा था। घर से कुछ दूर सड़क किनारे लगा जर्जर बिजली का खंभा टूटकर उसके ऊपर गिर गया। सिर पर खंभा गिरने से वह खून से लथपथ होकर बेहोश हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उसे सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पिता उमाशंकर ने बताया कि दो भाइयों व एक बहन में सबसे छोटा था। पिता कर्वी में सफाईकर्मी हैं। वह इंटर का छात्र था। घर में मां मुन्नी देवी है। अतर्रा कोतवाली प्रभारी कुलदीप तिवारी ने बताया कि खंभा गिरने से हादसा हुआ है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।

फिटनेस कराने पहुंचे स्कूली वाहन, ढाई बजे तक नहीं दिखे अफसर

बांदा, संवाददाता। संभागीय परिवहन कार्यालय में रविवार को वाहनों का फिटनेस कैंप लगाया गया। एक दिन पूर्व इसकी अधिकृत सूचना विभाग ने दी थी। स्कूल वाहनों के स्वामियों और स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी थी कि कैंप में वाहनों की फिटनेस नहीं कराई तो रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके पूर्व वाहन स्वामियों को नोटिस भी भेजा था। सुबह 10 बजे कैंप का समय बताया था। तयशुदा समय पर तमाम स्कूलों के चालक स्कूली वाहन लेकर आरटीओ कार्यालय के सामने खड़े हो गए, लेकिन न तो कैंप का पता था और न ही अधिकारियों का। रविवार दोपहर तकरीबन दो बजकर 15 मिनट पर संवाददाता आरटीओ कार्यालय पहुंचा तो वहां आरटीओ और एआरटीओ नहीं थे। दफ्तर में सन्नाटा था। कैमरे की फ्लश संभागीय परिवहन कार्यालय में चमकी तो वहां मौजूद बाबू कुछ कागज लेकर कार्यालय भवन से नीचे उतरते नजर आए और स्कूल वाहनों के कागजात चालकों से बटोरने लगे। आरटीओ, एआरटीओ और पीटीओ दोपहर ढाई बजे तक कार्यालय में नजर नहीं आए।

इंजीनियरिंग छात्रों ने सड़क पर लगाया जाम

संवाददाता। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों ने ईयर बैक का आरोप लगाते हुए सड़क पर वाहन खड़े कर जाम लगा दिया। जिससे आने–जाने वाले राहगीरों को परेशानी हुई। एएमयू में इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने विभाग के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। नाराज छात्रों ने बाइक लगाकर सड़क को बंद कर दिया।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।